

वेस्ट बैंक में रंगभेद (Apartheid)

मेरे पिछले निबंधों में मैंने मुख्य रूप से गाजा पर ध्यान केंद्रित किया है - एक ऐसा स्थान जो अब **आधुनिक मानव इतिहास में अभूतपूर्व आपदा** का सामना कर रहा है। विनाश का पैमाना चौंका देने वाला है: एक ऐसा क्षेत्र जो हिरोशिमा के आकार का केवल एक-तिहाई है, उस पर **सात परमाणु बमों** के बराबर विस्फोटक शक्ति से हमला किया गया है। मानव सभ्यता के सभी निशान मिटा दिए गए हैं। कम से कम **60,000 फिलिस्तीनियों** की मृत्यु की पुष्टि हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक पीड़ितों की संख्या **400,000** तक हो सकती है - जो गाजा की आबादी का लगभग **पांचवां हिस्सा** है।

विनाश का यह स्तर कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित कर सकता है कि वेस्ट बैंक में जीवन, जहां न तो हमारा है और न ही सशस्त्र प्रतिरोध, बेहतर है - एक ऐसा मॉडल जिसे फ्रांस और कई अरब सरकारों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की शर्त के रूप में प्रस्तावित किया है।

हालांकि, यह धारणा खतरनाक रूप से गलत है।

इस निबंध में, मैं **वेस्ट बैंक में कब्जे के तहत जीवन** के बारे में बात करना चाहता हूं - यह इसलिए नहीं कि यह अधिक शांतिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यह **एक धीमा, सुनियोजित उन्मूलन प्रणाली** है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो बमों और नाकेबंदी के माध्यम से नहीं, बल्कि नौकरशाही, भूमि की चोरी, रंगभेद कानूनों और उपनिवेशकों की निरंतर हिंसा के माध्यम से संचालित होती है।

रेंगता हुआ विलय (Creeping Annexation)

वेस्ट बैंक को मूल रूप से 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत एक अरब राज्य का हिस्सा बनना था - एक सतत फिलिस्तीनी क्षेत्र। यह दृष्टिकोण कभी साकार नहीं हुआ। आज जो मौजूद है वह न तो एक व्यवहार्य राज्य है और न ही एक सुसंगत क्षेत्र, बल्कि इजरायली नियंत्रण के विभिन्न स्तरों के तहत फिलिस्तीनी एन्क्लेव्स का एक खंडित और सिकुड़ता हुआ द्वीपसमूह है। यह कोई संयोग नहीं है। यह इजरायल की दशकों की जानबूझकर की गई नीतियों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य स्थायी क्षेत्रीय विस्तार, फिलिस्तीनियों का विस्थापन और भूमि का विलय है।

इजरायली सरकार ने वास्तव में वेस्ट बैंक को तीन प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया है:

- 1. वास्तव में विलय किए गए क्षेत्र** - ये क्षेत्र, विशेष रूप से बड़ी इजरायली बस्तियों के आसपास, पूरी तरह से इजरायल के नागरिक और सैन्य प्रशासन के अधीन हैं। इन्हें इजरायल के बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया गया है, इन्हें इजरायली नगरपालिका सेवाएं प्राप्त होती हैं, और इनकी निगरानी अक्सर इजरायली सेना के बजाय पुलिस द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले उपनिवेशक इजरायली नागरिक हैं जिन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण, मतदान का अधिकार और आवाजाही की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके फिलिस्तीनी पड़ोसी, जो अक्सर केवल कुछ सौ मीटर की दूरी पर रहते हैं, सैन्य कानून और रंगभेद जैसे प्रतिबंधों के तहत रहते हैं।
- 2. सक्रिय रूप से नस्लीय सफाई के अधीन क्षेत्र** - ये फिलिस्तीनी ग्रामीण क्षेत्र हैं जो विध्वंस, निष्कासन और उपनिवेशीकरण के लक्ष्य हैं। पूरे गांव - जैसे खान अल-अहमर, मसाफर यट्टा और एन समिया - बार-बार विध्वंस के आदेशों का सामना करते हैं। फिलिस्तीनी घरों को नियमित रूप से निर्माण परमिट से वंचित किया जाता है, उन्हें अवैध घोषित किया जाता है और इजरायल के नागरिक प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। इस बीच, इजरायली चौकियां - जो तकनीकी रूप से इजरायली कानून के तहत भी अवैध हैं - को बाद में वैध बनाया जाता है और सड़कों, पानी और बिजली से जोड़ा जाता है। जल आपूर्ति को उपनिवेशकों की ओर मोड़ दिया जाता है, जबकि फिलिस्तीनी समुदाय टैंकरों पर निर्भर हैं। पहुंच मार्गों को फिलिस्तीनियों के लिए बंद कर दिया जाता है और "केवल इजरायलियों के लिए" चिह्नित किया जाता है। चरागाह और जैतून के बगीचे जब्त कर लिए जाते हैं या दुर्गम बना दिए जाते हैं। सेना

के समर्थन या उदासीनता के साथ, उपनिवेशकों की हिंसा फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से भगाने का एक रणनीतिक उपकरण है।

3. **फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नाममात्र नियंत्रण वाले क्षेत्र (क्षेत्र A)** - ये क्षेत्र, जो ओस्लो समझौतों के अनुसार पूरी तरह से फिलिस्तीनी नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण में होने चाहिए, इजरायल द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से घिरी गेटो जैसी एन्क्लेव्स हैं। प्रवेश और निकास इजरायली चौकियों, बंद और कर्फ्यू के अधीन हैं। फिलिस्तीनी ramallah, नब्लस और हेब्रोन जैसे शहरों के बीच स्वतंत्र रूप से आवाजाही नहीं कर सकते बिना इजरायली सैन्य बाधाओं का सामना किए। फिलिस्तीनियों के लिए निषिद्ध सड़कें परिदृश्य को काटती हैं, बस्तियों को जोड़ती हैं और फिलिस्तीनी शहरों को अलग करती हैं। क्षेत्र A में भी, इजरायली छापे आम हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पास इन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं है। इसके सुरक्षा बल वास्तव में फिलिस्तीनी प्रतिरोध को दबाने और कब्जे के तहत स्थिरता बनाए रखने के लिए भर्ती किए गए हैं।

यह नियंत्रण मैट्रिक्स एक रेंगते हुए विलय का रूप बनाता है। इसे किसी एक कानून या घोषणा द्वारा चिह्नित नहीं किया जाता, बल्कि बस्ती ब्लॉकों, सैन्य क्षेत्रों, बाईपास सड़कों और नौकरशाही शासन के उपकरणों के निरंतर विस्तार द्वारा चिह्नित किया जाता है। फिलिस्तीनी उपस्थिति को अनिश्चित और अस्थायी बना दिया जाता है, जबकि इजरायली उपनिवेशकों की उपस्थिति स्थायी और निरंतर विस्तार करने वाली होती है।

वेस्ट बैंक में कोई “यथास्थिति” नहीं है। यथास्थिति एक गति है: पूर्ण इजरायली नियंत्रण और किसी भी संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को समाप्त करने की दिशा में एक धीमी, सुनियोजित गति। हर दिन, नक्शा थोड़ा बदलता है - एक और पहाड़ी जब्त की जाती है, एक और गांव अलग-थलग पड़ जाता है, एक और जैतून का बगीचा नष्ट हो जाता है। यह कोई जमा हुआ संघर्ष नहीं है। यह उपनिवेशीकरण की एक सक्रिय प्रक्रिया है।

वेस्ट बैंक में यात्रा: एक दैनिक जोखिम

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए, सबसे सामान्य यात्रा भी - स्कूल, काम, अस्पताल, या पड़ोसी गांव तक - **एक जानलेवा अनुभव** बन सकती है। इजरायली सैन्य चौकियां और उपनिवेशकों के लिए बाईपास सड़कें क्षेत्र को दर्जनों खंडित एन्क्लेव्स में विभाजित करती हैं। जो **10 मिनट की यात्रा** होनी चाहिए, वह घंटों ले सकती है या पूरी तरह से असंभव हो सकती है।

यात्रा करना एक **जोखिम** है, क्योंकि:

- **चौकियों की अप्रत्याशितता:** वेस्ट बैंक में **500 से अधिक स्थायी और अस्थायी चौकियां** हैं। इनमें से कोई भी बिना किसी चेतावनी के मिनटों या दिनों के लिए बंद हो सकती है। सैनिक यात्रियों को मनमाने ढंग से हिरासत में ले सकते हैं, वाहनों की तलाशी ले सकते हैं या बिना किसी स्पष्टीकरण के आवाजाही से इनकार कर सकते हैं।
- **सैन्य बंद:** पूरे क्षेत्रों को अक्सर “बंद सैन्य क्षेत्र” घोषित किया जाता है, अक्सर विरोध प्रदर्शनों या उपनिवेशकों द्वारा शुरू की गई घटनाओं के जवाब में। इन बंद के दौरान, फिलिस्तीनी **अपने घरों में कैद** हो जाते हैं, बिना काम, स्कूल या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के।
- **उपनिवेशकों की सड़कें और वाहन प्रतिबंध:** वेस्ट बैंक की कई सड़कें **केवल इजरायली उपनिवेशकों के लिए आरक्षित** हैं। फिलिस्तीनियों को इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है और उन्हें लंबे, खराब रखरखाव वाले और कड़ाई से निगरानी वाले मार्गों से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वाहनों की जब्ती और जुर्माना आम हैं।
- **मनमानी गिरफ्तारियां और हिरासत:** किसी भी चौकी पर, एक फिलिस्तीनी को **बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है**, खासकर यदि उनका नाम सेना के डेटाबेस में दिखाई देता है - इसमें **नाबालिग, छात्र या कार्यकर्ता** शामिल हो सकते हैं। हिरासत का मतलब सैन्य जेल में दिन या महीने हो सकता है, अक्सर बिना किसी मुकदमे के।
- **उत्पीड़न और अपमान:** सैनिक नियमित रूप से फिलिस्तीनियों को मौखिक अपमान, आक्रामक तलाशी और घंटों की देरी के अधीन करते हैं। इस व्यवहार के लिए कोई कानूनी उपाय या जवाबदेही नहीं है।
- **घात और गोलीबारी:** ऐसे प्रलेखित मामले हैं जहां इजरायली सैनिकों या उपनिवेशकों ने **वाहनों पर गोलीबारी** की है, जिन्हें वे संदिग्ध मानते थे या जिनके ड्राइवर पर्याप्त तेजी से नहीं रुके। ये घटनाएं अक्सर घातक होती हैं, और जांच - यदि शुरू होती है - शायद ही कभी परिणाम देती है।

- **सड़कों पर उपनिवेशकों की हिंसा:** उपनिवेशक नियमित रूप से फिलिस्तीनी वाहनों पर पत्थर फेंकते हैं, सड़कों को बिना सजा के ब्लॉक करते हैं और यहां तक कि वाहनों और यात्रियों पर हमला करते हैं। इजरायली बल अक्सर किनारे खड़े रहते हैं या उपनिवेशकों की रक्षा करते हैं।

इस खंडित प्रणाली में, **आवाजाही की स्वतंत्रता मौजूद नहीं है**। एक गांव से दूसरे गांव तक यात्रा करने की क्षमता - अस्पताल, परिवार से मिलने, माल ढोने के लिए - **सैन्य आदेशों, उपनिवेशकों की आक्रामकता और नौकरशाही नियंत्रण** की लगातार बदलती मैट्रिक्स के अधीन है।

यह केवल एक असुविधा नहीं है; यह एक **सुनियोजित गला घोटने की प्रणाली** है, जिसे सामान्य जीवन को असंभव बनाने, समुदायों को अलग करने और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से भगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विस्थापन के तंत्र: उपनिवेशकों की हिंसा

कब्जे वाले वेस्ट बैंक में, जबरन विस्थापन हमेशा आधिकारिक घोषणाओं या प्रत्यक्ष सैन्य आदेशों के माध्यम से नहीं होता। यह अक्सर इजरायली उपनिवेशकों द्वारा आयोजित एक धीमे, सुनियोजित आतंक अभियान के माध्यम से होता है - एक ऐसा अभियान जिसे सहन किया जाता है, संरक्षित किया जाता है और अंततः पूरे इजरायली राज्य तंत्र द्वारा समर्थित किया जाता है। यह हिंसा यादृच्छिक नहीं है। यह व्यवस्थित, रणनीतिक और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकालने के लिए डिज़ाइन की गई है।

प्रक्रिया आम तौर पर तीन बढ़ते चरणों में सामने आती है:

1. डराना और निजी घरों में घुसपैठ

पहला चरण अक्सर उपनिवेशकों द्वारा फिलिस्तीनी संपत्तियों पर बिना निमंत्रण के घुसपैठ के साथ शुरू होता है। वे दिन के उजाले में आते हैं, कभी-कभी समूहों में, अक्सर हथियारों से लैस। वे एक फिलिस्तीनी परिवार के घर में घुस सकते हैं और लिविंग रूम में बैठ सकते हैं जैसे कि वह उनका हो। वे रसोई में खाना खाते हैं, परिवार को अपमानित करते हैं, नस्लीय गालियां चिल्लाते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, ग्रैफिटी स्प्रे करते हैं या फर्श पर पेशाब करते हैं। ये कार्य गहरे अपमानजनक हैं - न केवल गोपनीयता का उल्लंघन, बल्कि नियंत्रण और भय पैदा करने के जानबूझकर किए गए प्रयास।

ये घुसपैठें अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। ये बार-बार और लक्षित होती हैं, जिनका उद्देश्य निवासियों की इच्छाशक्ति को तोड़ना है। संदेश स्पष्ट है: “यह अब आपकी जमीन नहीं है।” और फिलिस्तीनी जानते हैं कि यदि वे प्रतिरोध करते हैं, तो वे गिरफ्तारी, चोट या इससे भी बदतर जोखिम में डालते हैं - घुसपैठियों को पीछे हटाने के लिए नहीं, बल्कि “उकसावे” या “उपनिवेशकों पर हमले” के लिए।

2. आजीविका का विनाश

यदि डराने से परिवार को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तो उपनिवेशक अगले चरण में बढ़ते हैं, उनकी आजीविका पर हमला करके। वे दशकों पुराने जैतून के पेड़ों को काट देते हैं, जो न केवल आय का स्रोत हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी हैं। वे फसलों को जहर देते हैं या उखाड़ फेंकते हैं, झुंडों को तितर-बितर करते हैं, भेड़ों को चुराते हैं या मार देते हैं। पानी के टैंक और सिंचाई पाइप - जो इजरायल द्वारा नियंत्रित जल नेटवर्क तक पहुंच के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं - नष्ट कर दिए जाते हैं या गोलियों से छलनी कर दिए जाते हैं। कुएं पत्थरों, कंक्रीट या मलबे से भर दिए जाते हैं।

यह विनाश यादृच्छिक बर्बरता नहीं है। यह कृषि जीवन को असंभव बनाने की रणनीति है। बिना फसलों, बिना पशुधन, बिना पानी के, फिलिस्तीनी परिवारों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं और आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है। लक्ष्य केवल नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जमीन को इसके लोगों से खाली करना है।

3. विध्वंस और आगजनी

अंत में, जब फिलिस्तीनी फिर भी जाने से इनकार करते हैं, तो उपनिवेशक उनके घरों को निशाना बनाते हैं। कभी-कभी वे बुलडोजर और उत्खनन मशीनें लाते हैं। कभी-कभी वे रात में घरों में आग लगा देते हैं, परिवारों को अंदर फंसाते हैं या बिना

कुछ लिए भागने के लिए मजबूर करते हैं। वीडियो और प्रत्यक्षदर्शी खाते जले हुए घरों, चुराए गए सामान और पूरे गांवों को राख में बदलने की घटनाओं को दर्ज करते हैं।

यह विनाश अक्सर एक स्पष्ट पैटर्न का पालन करता है: एक दिन आगजनी या विध्वंस, अगले दिन एक चौकी का विस्तार। जमीन साफ होने के बाद, उपनिवेशक अंदर आते हैं - कारवां, बाड़ और सभास्थल स्थापित करते हैं। इन अवैध चौकियों को फिर सड़कों, बिजली और पानी से जोड़ा जाता है। वे जल्दी से “सामान्यीकृत” हो जाते हैं, इजरायली सेना द्वारा संरक्षित होते हैं और अंततः इजरायली सरकार द्वारा पीछे की तारीख में वैध कर दिए जाते हैं।

दण्डमुक्ति और दमन

इन सभी चरणों में - घरों में घुसपैठ, आजीविका का विनाश और विध्वंस - फिलिस्तीनियों को संदेश एक ही है: छोड़ दो या नष्ट हो जाओ।

और हर मामले में **दण्डमुक्ति की गारंटी** होती है। **फिलिस्तीनी प्राधिकरण** का इन क्षेत्रों में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह उपनिवेशकों का सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह जानता है कि इससे इजरायली प्रतिशोध होगा।

इजरायली पुलिस और सेना नियमित रूप से आंखें मूंद लेते हैं - सिवाय जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध करते हैं। तब प्रतिक्रिया तेज होती है: गिरफ्तारियां, पिटाई, असली गोलियों से गोलीबारी, सैन्य छापे। प्रतिरोध को अपराधी बनाया जाता है, जबकि उपनिवेशकों की हिंसा को माफ कर दिया जाता है या इनकार किया जाता है। पीड़ितों को न्याय तक कोई पहुंच नहीं है।

परिणामस्वरूप, उपनिवेशकों के लिए अराजकता का एक शासन और फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक कानूनी युद्ध है - दण्डमुक्ति और दमन का एक दोहरा तंत्र। उपनिवेशक विलय के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं, वह करते हैं जो इजरायली सरकार अभी खुले तौर पर नहीं कर सकती: फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन निकालना।

यह सहज या जैविक नहीं है। यह एक नीति है। एक विधि। एक ऐसी रणनीति जो नागरिकों द्वारा निष्पादित की जाती है, राज्य द्वारा स्वीकृत होती है और सेना द्वारा लागू की जाती है।

हथियार के रूप में पानी

पानी, जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता, वेस्ट बैंक में वर्चस्व का एक उपकरण बन गया है। हालांकि समय के साथ रणनीतियां विकसित हुई हैं, रणनीति वही रहती है: फिलिस्तीनी अस्तित्व को असहनीय बनाना। युद्ध के हथियार के रूप में पानी का उपयोग - पहले खुले तौर पर जैविक, अब संरचनात्मक और बुनियादी ढांचागत - इजरायली कब्जे के शासन का एक आधार है।

ऐतिहासिक समानताएं: जहर से नियंत्रण तक

नकबा के शुरुआती दिनों में, इजरायली मिलिशिया और वैज्ञानिकों ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ जैविक युद्ध की योजना बनाई और कभी-कभी निष्पादित की। सबसे कुख्यात मामलों में से एक में शरणार्थियों की वापसी को रोकने के लिए फिलिस्तीनी गांवों के कुओं को **टाइफाइड बैक्टीरिया** से जहर देना शामिल था। यह कोई मिथक या “रक्तरंजित यहूदी-विरोधी आरोप” नहीं है - यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित ऐतिहासिक तथ्य है। इजरायली अभिलेखागार इन अभियानों की पुष्टि करते हैं, जिसमें **1948 में एकर और एन करीम गांव** में एक घटना शामिल है, जहां जल स्रोतों को जानबूझकर दूषित किया गया था।

इस कृत्य की भयावहता यहूदी इतिहास में इसके प्रतिध्वनि से और बढ़ जाती है: **एनी फ्रैंक**, कई अन्य लोगों की तरह, गैस चैंबर में नहीं मरी, बल्कि **टाइफस** से, जो एक जलजनित बीमारी है, बर्गन-बेलसन में। यह कि एक राज्य जो होलोकास्ट के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, ने बाद में एक अन्य लोगों के खिलाफ समान रणनीतियों का उपयोग किया, यह एक भयानक ऐतिहासिक विडंबना है।

आधुनिक रणनीतियां: बर्बरता और लूट

आज, रणनीति जैविक युद्ध से बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ और लूट में बदल गई है। उपनिवेशक - अक्सर दण्डमुक्ति के साथ और कभी-कभी सैन्य सुरक्षा के तहत - **वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जल प्रणालियों को नष्ट** करते हैं:

- वे **नगरपालिका जल टैंकों में नहाते हैं**, आपूर्ति को दूषित करते हैं।
- वे **सिंचाई पाइपों को नष्ट** करते हैं और झरनों तक पहुंच मार्गों को अवरुद्ध करते हैं।
- वे **छतों पर जल टैंकों में छेद करते हैं**, जिससे गर्मी की शुष्कता में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है।
- वे **कुओं को पत्थरों, कंक्रीट या मलबे से भर देते हैं**, जिससे वे उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं।

जुलाई 2025 में, उपनिवेशकों ने **एन समिया के पास 30 से अधिक फिलिस्तीनी गांवों की जल आपूर्ति को हटा दिया** - महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि **नजदीकी बस्ती में एक निजी स्विमिंग पूल भरने के लिए**। पूरे समुदायों ने अपनी एकमात्र पेयजल स्रोत खो दी, जबकि उपनिवेशक विलासिता में डुबकी लगाते थे। यह लापरवाही नहीं है; यह वर्चस्व की घोषणा है।

संस्थागत नियंत्रण: मेकॉरोट और सैन्य आदेश

उपनिवेशकों की बर्बरता एक व्यापक इजरायली राज्य जल संसाधनों के नियंत्रण प्रणाली के ढांचे में होती है - और इसके द्वारा संभव बनाई जाती है। यह शासन **सैन्य आदेश 158** में निहित है, जो 1967 में कब्जे की शुरुआत के कुछ हफ्तों बाद जारी किया गया था। यह फिलिस्तीनियों को किसी भी नई जल स्थापना या मरम्मत के लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये परमिट लगभग कभी नहीं दिए जाते।

इजरायल वेस्ट बैंक के जल संसाधनों का लगभग 80-85% नियंत्रित करता है, जिसमें बड़े भूजल जलाशय, झरने और कुएं शामिल हैं। राष्ट्रीय जल कंपनी **मेकॉरोट** वितरण की देखरेख करती है। परिणाम एक स्पष्ट असमानता है:

- **52%** निकाला गया पानी स्वयं इजरायल में जाता है।
- **32%** बस्तियों में जाता है - जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं।
- केवल **16%** वेस्ट बैंक में **लाखों फिलिस्तीनियों** के लिए रहता है।

बस्तियां हरी-भरी लॉन, सिंचित खेतों और स्विमिंग पूल का आनंद लेती हैं। इस बीच, फिलिस्तीनी गांवों को पानी की राशनिंग करनी पड़ती है, कभी-कभी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल **20-50 लीटर** प्राप्त होता है, जो **विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित 100 लीटर न्यूनतम** से बहुत कम है।

भूजल जलाशयों की लूट और पर्यावरण विनाश (Ecocide)

सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक **पहाड़ी भूजल जलाशय** है, जो वेस्ट बैंक और इजरायल में फैला हुआ है। इजरायल की गहरी ड्रिलिंग - उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, जिन्हें फिलिस्तीनियों को उपयोग करने की अनुमति नहीं है - जलाशय की स्थायी रूप से उत्पादन करने की क्षमता से कहीं अधिक पानी निकालती है। इस अतिदोहन के कारण **जॉर्डन घाटी** में विशेष रूप से कई **फिलिस्तीनी कुएं सूख गए हैं या खारे हो गए हैं**।

अल-औजा और बरदला जैसे गांवों में, पारंपरिक कृषि लगभग असंभव हो गई है। कभी समृद्ध खेत अब बंजर हैं, और चरवाहों को निर्जलीकरण के कारण अपने पशुधन को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। स्वयं भूमि मर रही है - यह केवल रंगभेद नहीं है, यह **पर्यावरण विनाश** है।

बारिश का अपराधीकरण

यहां तक कि आकाश भी स्वतंत्र नहीं है। **वर्षा जल संग्रह**, फिलिस्तीनी कृषि समुदायों में एक सदियों पुरानी प्रथा, को अक्सर अपराधी बनाया जाता है। जो फिलिस्तीनी बिना परमिट के टैंकों का निर्माण करते हैं या वर्षा जल एकत्र करते हैं, उन्हें **विध्वंस आदेश**, जुर्माना या जब्ती का सामना करना पड़ता है। इजरायली अधिकारियों ने "अनधिकृत" माने जाने वाले क्षेत्रों में दर्जनों टैंकों को नष्ट कर दिया है। एक कुख्यात मामले में, सैनिकों ने **बेडौइन गांव में वर्षा जल टैंकों की दीवारों को छेद दिया**, जिससे एकत्रित पानी रेत में बह गया।

पानी शक्ति है

पानी का यह सैन्यीकरण कमी से संबंधित नहीं है - यह शक्ति से संबंधित है। इजरायल के पास साझा करने के लिए पर्याप्त से अधिक पानी है। यह जो फिलिस्तीनियों से वंचित करता है वह केवल H₂O नहीं है, बल्कि **गरिमा, स्थिरता और उनकी जमीन पर बने रहने का अधिकार** है। पानी को नियंत्रण का साधन और वर्चस्व का प्रतीक बनाकर, कब्जा दैनिक जीवन को एक थकाऊ, अपमानजनक अस्तित्व के लिए संघर्ष में बदल देता है।

यह पर्यावरण का कुप्रबंधन नहीं है। यह रणनीतिक अभाव है - पाइपों और पंपों के माध्यम से लड़ी जाने वाली एक युद्ध, जिसका उद्देश्य उन लोगों के लिए जीवन को न रहने योग्य बनाना है जिन्हें अनावश्यक माना जाता है।

पारिस्थितिकी का परिवर्तन

इजरायली अक्सर बाइबिल की बयानबाजी का हवाला देते हुए और स्वयं को “वापसी करने वाले स्वदेशी” के रूप में प्रस्तुत करते हुए, भूमि के साथ गहरे पैतृक संबंधों का दावा करते हैं। हालांकि, उनकी पारिस्थितिक छाप एक अलग कहानी बताती है - न केवल लोगों के बल्कि स्वयं प्रकृति के हिंसक विस्थापन की कहानी। परिदृश्य को बलपूर्वक एक उपनिवेशी बस्ती विचारधारा को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्जनन किया जाता है, न कि पर्यावरण में प्रामाणिक जड़ें जमाने के लिए। यहां तक कि पेड़ भी इस झूठ के खिलाफ गवाही देते हैं।

स्वदेशी जीवन का उन्मूलन

सदियों से, फिलिस्तीनी गांवों ने स्थानीय जलवायु और भूभाग के साथ गहरे सामंजस्य में कृषि के माध्यम से स्वयं को बनाए रखा। जैतून के पेड़ - कुछ एक हजार साल से अधिक पुराने - निरंतरता और संस्कृति के जीवित अभिलेखागार के रूप में खड़े थे। साइट्रस बाग, अंजीर के पेड़, अनार के बगीचे और सीढ़ीदार पहाड़ी ढलानें मानव जीवन और भूमध्यसागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक नाजुक सामंजस्य को मूर्त रूप देती थीं।

हालांकि, नकबा और निरंतर भूमि जब्ती के बाद, ये स्वदेशी पेड़ **उखाड़ दिए जाते हैं** - अक्सर शाब्दिक रूप से। कुछ मामलों में, हटाने रणनीतिक होता है: जैतून के बगीचों को बस्तियों या सैन्य क्षेत्रों के लिए रास्ता बनाने के लिए नष्ट कर दिया जाता है। अन्य में, उन्हें **नस्लीय सफाई के सबूतों को छिपाने** के लिए हटाया जाता है, फिलिस्तीनी घरों के खंडहरों को जंगल की आड़ में छिपाया जाता है। इजरायली राज्य और **यहूदी राष्ट्रीय कोष (JNF)** जैसे संस्थानों ने स्वदेशी प्रजातियों के साथ नहीं, बल्कि **यूरोपीय पाइंस** के साथ - तेजी से बढ़ने वाले, बंजर और क्षेत्र के लिए विदेशी - बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान चलाए हैं।

पारिस्थितिक उपनिवेशवाद

ये पाइन फल नहीं देते। वे स्थानीय खाद्य प्रणालियों, वन्यजीवों या जैव विविधता को समर्थन नहीं दे सकते। इससे भी बदतर, वे अपनी राल और गिरी हुई सुइयों के माध्यम से **मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं**, जिससे स्वदेशी पौधों को समर्थन देने वाले नाजुक पोषक संतुलन बिगड़ जाता है। एक बार उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए शत्रुतापूर्ण हो जाती है - जड़ी-बूटियां, सब्जियां और जैतून, खजूर और बादाम जैसे स्वदेशी पेड़ जड़ नहीं जमा सकते।

यह केवल खराब पर्यावरण नीति नहीं है; यह **पारिस्थितिक उपनिवेशवाद** है - भूमि को यूरोपीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने के लिए बदलना, जो स्थानीय ज्ञान या स्थिरता से कटा हुआ है। जहां फिलिस्तीनी जीवन की खेती करते थे, वहां इजरायली नीति बंजरता थोपती है। जहां परिदृश्य कभी भोजन और अर्थ प्रदान करता था, वह अब ज्वलनशीलता प्रदान करता है।

प्रकृति का प्रतिरोध

लेकिन प्रकृति भी प्रतिरोध करती है। यूरोपीय पाइंस की एकल-फसली खेती **अत्यधिक ज्वलनशील** होती है - उनकी राल से भरी सुइयां, सूखी शाखाएं और घने विकास पैटर्न आग के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। हर गर्मी में, **जंगल की आग इन कृत्रिम जंगलों में भड़कती है**, जो न केवल उनके आसपास बनी बस्तियों को बल्कि व्यापक क्षेत्र को भी खतरे में डालती है। आग अक्सर **शहरों और चौकियों से बड़े पैमाने पर निकासी** का कारण बनती है, आकाश को धुएं से भर देती है और विशाल क्षेत्रों को जला हुआ और उपयोग के लिए अनुपयुक्त छोड़ देती है।

ये पारिस्थितिक आपदाएं इजरायल के पर्यावरण परिवर्तन की अस्थिर नींव को उजागर करती हैं। पेड़, दीवारों और चौकियों की तरह, एक लोगों को मिटाने के लिए हैं - लेकिन ऐसा करने में, वे नई असुरक्षाएं पैदा करते हैं। आग उपनिवेशक और राज्य के बीच भेद नहीं करती। वे मिथक को जंगल के साथ निगल लेती हैं।

अंतरराष्ट्रीय बचाव

जब आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है - जैसा कि **माउंट कार्मेल (2010)**, **जेरूसलम हिल्स (2021)** और **गैलीली (2023)** में हुआ - इजरायल अक्सर खुद को **अंतरराष्ट्रीय सहायता की भीख मांगते हुए** पाता है। वही राज्य जो गाजा पर नाकेबंदी करता है और बिना पछतावे के फिलिस्तीनी भूमि का विलय करता है, जल्दी से **विदेशी सरकारों से अग्निशमन विमान, उपकरण और सहायता** भेजने की मांग करता है। विडंबना चौंकाने वाली है: जो नीतियां भूमि को विकृत करती हैं और इसके लोगों को विस्थापित करती हैं, वे **राज्य की अपनी लचीलापन को भी कमजोर करती हैं**।

जली हुई धरती की नीति

स्वदेशी पारिस्थितिकी को विदेशी, नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों से बदलना पूरे सिव्वादी परियोजना का एक रूपक है: एक उपनिवेशी बस्ती विचारधारा जो एक ऐसी भूमि पर जड़ जमाने की कोशिश करती है जो प्रतिरोध करती है, एक ऐसा लोग जो बने रहता है और एक प्राकृतिक व्यवस्था जिसे अनिश्चित काल तक दबाया नहीं जा सकता। पेड़ केवल मूक गवाह नहीं हैं। वे पीड़ित हैं - और कभी-कभी योद्धा।

अंतरराष्ट्रीय कानून के निहितार्थ

फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्थिति केवल नैतिक रूप से असमर्थनीय नहीं है - यह **कानूनी रूप से आपराधिक** है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और बाध्यकारी संधियों के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजरायल की कार्रवाइयां **गंभीर उल्लंघनों** की एक श्रृंखला का गठन करती हैं, जिनमें से कई **युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों** के स्तर तक पहुंचती हैं।

1. अवैध जनसंख्या हस्तांतरण

1949 की चौथी जेनेवा संधि, अनुच्छेद 49(6), स्पष्ट रूप से एक कब्जे वाली शक्ति को **अपनी नागरिक आबादी के हिस्सों को कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने** से रोकती है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजरायली बस्तियां, जहां 700,000 से अधिक उपनिवेशक रहते हैं, इस प्रावधान का प्रत्यक्ष उल्लंघन हैं। ये बस्तियां केवल “विवादित पड़ोस” नहीं हैं - ये **कब्जे वाली भूमि की व्यवस्थित उपनिवेशीकरण** हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून की सबसे मूलभूत मानदंडों में से एक के विपरीत हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकार राय (2024)

2024 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए एक बाध्यकारी सलाहकार राय जारी की, जिसमें पुनः पुष्टि की गई कि:

- वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजरायली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं;
- सभी उपनिवेशकों को हटाया जाना चाहिए;
- इजरायल को लंबे समय तक कब्जे, भूमि जब्ती, संसाधन शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए फिलिस्तीनी लोगों को मुआवजा देना है।

ICJ ने यह भी दोहराया कि **तृतीय पक्ष देशों को इजरायल की नीतियों द्वारा बनाई गई अवैध स्थिति को मान्यता न देने या सहायता न करने की कानूनी जिम्मेदारी** है। दूसरे शब्दों में, सांठगांठ - चाहे व्यापार, हथियारों की बिक्री या राजनयिक कवर के माध्यम से - स्वयं अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस राय को **भारी बहुमत** से अपनाया, जिससे इसे **अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून के तहत मजबूत कानूनी वजन** प्राप्त हुआ। हालांकि सलाहकार राय स्वयं लागू करने योग्य नहीं हैं, वे **अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहमति को संहिताबद्ध** करती हैं और मौजूदा संधियों के तहत राज्यों की जिम्मेदारियों की पुष्टि करती हैं।

3. प्राकृतिक संसाधनों का अवैध शोषण

1907 के हेग नियम (अनुच्छेद 55-56) और **चौथी जेनेवा संधि** के अनुसार, एक कब्जे वाली शक्ति को **अस्थायी प्रशासक** के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसे **कब्जे वाले क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण या स्थायी रूप से समाप्त करने** से निषिद्ध किया गया है।

इजरायल की प्रथाएं - मेकॉरोट के माध्यम से वेस्ट बैंक के पानी के एकाधिकार से लेकर, भूजल जलाशयों तक फिलिस्तीनियों की पहुंच को प्रतिबंधित करने और उपनिवेशकों के विशेष उपयोग के लिए संसाधनों को मोड़ने तक - **व्यवस्थित लूट** का गठन करती हैं। पानी से वंचित करना और कृषि प्रणालियों का विनाश **लूट** के समान है, जो **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संनियम के अनुच्छेद 8(2)(b)(xvi)** के तहत युद्ध अपराध है।

4. जबरन विस्थापन और घरों का विध्वंस

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून **जबरन विस्थापन** को निषिद्ध करता है, सिवाय तत्काल सुरक्षा या मानवीय कारणों के, और वह भी केवल अस्थायी रूप से। **रोम संनियम** (अनुच्छेद 7(1)(d)) "**आबादी का निर्वासन या जबरन हस्तांतरण**" को **मानवता के खिलाफ अपराध** के रूप में वर्गीकृत करता है, जब यह एक व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में किया जाता है।

इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी घरों का नियमित विध्वंस, शेख जर्जरह जैसे क्षेत्रों में निष्कासन आदेश और मसाफर यट्टा जैसे क्षेत्रों में जबरन विस्थापन - अक्सर बस्तियों के विस्तार या सैन्य क्षेत्रों की घोषणा के लिए - **इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से फिट बैठता है।**

5. मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में रंगभेद

वेस्ट बैंक में इजरायली शासन का सबसे गंभीर कानूनी वर्गीकरण **रंगभेद** है - एक **संस्थागत नस्लीय वर्चस्व** प्रणाली। फिलिस्तीनी और इजरायली उपनिवेशक **पूरी तरह से अलग कानूनी प्रणालियों** के तहत रहते हैं:

- **फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य कानून** के अधीन हैं, सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है, आवाजाही की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है और सामूहिक दंड के अधीन हैं।
- **उपनिवेशक**, जो अक्सर केवल कुछ मीटर की दूरी पर रहते हैं, **इजरायली नागरिक कानून** के अधीन हैं, पूर्ण अधिकार और संरक्षण का आनंद लेते हैं और लगभग पूर्ण दण्डमुक्ति के साथ कार्य करते हैं।

यह दोहरी कानूनी प्रणाली, व्यवस्थित भूमि लूट, अलगाव और राजनीतिक अधिकारों के दमन के साथ मिलकर, निम्नलिखित के अनुसार **रंगभेद की कानूनी परिभाषा** को पूरा करती है:

- **रंगभेद अपराध के दमन और दंड के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि (1973);**
- **ICC के रोम संनियम** (अनुच्छेद 7(2)(h));
- और **अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून**, जो नस्लीय भेदभाव और वर्चस्व को निषिद्ध करता है।

रंगभेद केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं है - यह **मानवता के खिलाफ एक अपराध** है, और जो इसे डिज़ाइन करते हैं, लागू करते हैं या समर्थन करते हैं, वे **अंतरराष्ट्रीय अभियोजन** के अधीन हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारियां

वेस्ट बैंक में इजरायल का कब्जा केवल एक अनसुलझा राजनीतिक विवाद नहीं है। यह एक **आपराधिक उद्यम** है, जो हिंसा द्वारा कायम है, भेदभावपूर्ण कानूनों के नेटवर्क द्वारा संभव बनाया गया है और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों के

उल्लंघनों द्वारा समर्थित है। कानूनी ढांचा असंदिग्ध है: जो हो रहा है वह अवैध है, और विश्व को **एक स्पष्ट जिम्मेदारी** है - न केवल इसकी निंदा करने की, बल्कि कार्रवाई करने की।

इसमें शामिल है:

- **संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों** को लागू करना;
- **अंतरराष्ट्रीय जांच और अभियोजन** का समर्थन करना;
- **कब्जे वाली शक्ति को सैन्य, आर्थिक और राजनयिक समर्थन** समाप्त करना;
- और **फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और मुआवजा** सुनिश्चित करना।

अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सार्थक है जब इसे लागू किया जाता है। और फिलिस्तीन में, इसका प्रवर्तन लंबे समय से अतिदेय है।

अंतरराष्ट्रीय सांठगांठ और प्रवर्तन की विफलता

न्याय, गरिमा और आत्मनिर्णय के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष को अक्सर एक स्थानीय या क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में, यह एक व्यापक ऐतिहासिक चाप का हिस्सा है - जो **17वीं और 18वीं सदी के यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ प्रबुद्धता के संघर्ष** को प्रतिबिंबित करता है। उस समय, जैसे अब, एक शासक शक्ति ने **दैवीय जनादेश** का दावा किया ताकि शासन, जब्ती और यहां तक कि यह तय करने का अधिकार हो कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। तब यह राजा थे जो ईश्वर की इच्छा का आह्वान करते थे; अब यह एक राज्य है जो एक पूरे लोगों के उपनिवेशीकरण और अधीनता को सही ठहराने के लिए दैवीय अधिकार का आह्वान करता है।

जिसे कभी **राजाओं का दैवीय अधिकार** कहा जाता था, वह **उपनिवेशकों का दैवीय अधिकार** बन गया है। लेकिन यूरोपीय राजतंत्रों के विपरीत, जो बड़े पैमाने पर इतिहास की औपचारिक अवशेष बन गए हैं, फिलिस्तीन पर इजरायल का शासन **निरंकुश वर्चस्व का एक पुरातन अवशेष** बना हुआ है, जो ऐसी संस्थाओं द्वारा जवाबदेही से अलग-थलग है जो ऐसी दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए बनाई गई थीं।

सुरक्षा परिषद का पक्षाघात

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के अनुसार, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** को **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** के फैसलों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि, जब ICJ ने 2024 में अपनी सलाहकार राय में घोषणा की कि इजरायली बस्तियां अवैध हैं और इन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, तो सुरक्षा परिषद ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि **संयुक्त राज्य**, एक स्थायी सदस्य, अपने वीटो का उपयोग करके **इजरायल को सभी परिणामों से बचाता** रहा है।

दशकों से, संयुक्त राज्य ने **इजरायल के अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों की निंदा करने वाली दर्जनों प्रस्तावों पर वीटो** लगाया है, जिससे सैंक्शनों, युद्धविराम या स्वतंत्र जांच की मांगें अवरुद्ध हो गई हैं। यह सैद्धांतिक कूटनीति नहीं है - यह **न्याय की व्यवस्थित रुकावट** है। अपने वीटो के माध्यम से, वाशिंगटन ने सुरक्षा परिषद को **फिलिस्तीनी अधिकारों का कब्रिस्तान** बना दिया है।

यूरोपीय पाखंड: जर्मनी और यूरोपीय संघ

जबकि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में रक्षा की भूमिका निभाता है, **जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य** एक अधिक सूक्ष्म खेल खेलते हैं। जर्मनी - अपने नाजी अतीत से प्रेतवाधित - ने इजरायल के बिना शर्त समर्थन को **राज्य सिद्धांत** बना दिया है, भले ही यह समर्थन **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों** और **नरसंहार संधि** के तहत इसकी कानूनी जिम्मेदारियों के साथ विरोधाभास में हो। जब इजरायल गाजा को भूखा रखता है और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करता है, तो जर्मनी हथियार, धन और राजनयिक कवर प्रदान करता है - साथ ही पर्दे के पीछे काम करके **यूरोपीय संघ स्तर पर सैंक्शनों या व्यापार प्रतिबंधों को रोकता** है।

इसने प्रभावी रूप से **अंतरराष्ट्रीय कानून को स्वयं एक रंगभेद प्रणाली** में बदल दिया है, जहां प्रवर्तन अपराध की गंभीरता पर नहीं, बल्कि अपराधी की पहचान पर निर्भर करता है। वे कार्य जो **रूस, ईरान या म्यांमार** द्वारा किए जाने पर **निंदा**,

सैंक्शनों या अभियोजन को प्रेरित करेंगे, जब इजरायल द्वारा किए जाते हैं तो **पवित्र** हो जाते हैं। संदेश स्पष्ट है: **कुछ जीवन दूसरों से अधिक मूल्यवान हैं**, और कुछ राज्य कानून से ऊपर हैं।

वैश्विक वैधता संकट

इस पाखंड के विनाशकारी परिणाम हैं - न केवल फिलिस्तीनियों के लिए, बल्कि **पूरे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की विश्वसनीयता** के लिए। **रोम संनियम** का क्या अर्थ है यदि इसका प्रवर्तन चयनात्मक है? **संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों** का क्या वजन है जब वे कुछ राज्यों के खिलाफ लागू किए जाते हैं, लेकिन दूसरों के खिलाफ नहीं? नरसंहार या रंगभेद के पीड़ितों को क्या आशा हो सकती है जब **सबसे शक्तिशाली राष्ट्र खुले तौर पर न्याय को कमजोर करते हैं**?

यह केवल सांठगांठ नहीं है - यह **सहयोग** है। परिणामों को रोककर, ये सरकारें तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि **अपराध के सक्रिय सुविधाकर्ता** हैं।

दैवीय अपवादिता के मिथक का अंत

यह समय है कि इस धारणा को समाप्त किया जाए कि **“ईश्वर का चुना हुआ लोग गलत नहीं कर सकते”** - एक मिथक जिसे **उपनिवेशीकरण, सामूहिक विस्थापन और रंगभेद को सही ठहराने के लिए हथियार बनाया गया है**। किसी भी राज्य को - उसकी इतिहास, धर्म या पहचान के बावजूद - अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने, एक लोगों को वंचित करने या अपने कार्यों के परिणामों से मुक्त होने का अधिकार नहीं है।

“फिर कभी नहीं” का वादा सार्वभौमिक होना था। केवल **“यहूदियों के लिए फिर कभी नहीं”**, बल्कि **किसी के लिए भी फिर कभी नहीं** - कभी नहीं। यह वादा खोखला लगता है जब इसे **दमन को रोकने** के बजाय **सही ठहराने** के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की ओर

अब हमें और अधिक बयानबाजी की नहीं, बल्कि **एक धर्मनिरपेक्ष, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था** की आवश्यकता है, जहां **अंतरराष्ट्रीय कानून सभी पर समान रूप से लागू हो** - जिसमें सहयोगी, इजरायल और उपनिवेशी बस्ती शासन शामिल हैं। केवल जब कानून को निडरता और निष्पक्षता से लागू किया जाता है, तभी न्याय एक नारे से अधिक हो सकता है।

दुनिया रवांडा में बहुत लंबे समय तक चुप रही। बोस्निया में। म्यांमार में। और अब फिलिस्तीन में। हर बार, अंतरराष्ट्रीय कानून की संस्थाएं परीक्षा में हैं। हर बार, उनकी विफलता पीड़ितों के खून में लिखी जाती है।

इतिहास मौन को माफ नहीं करेगा। यह दोहरे मापदंडों को सही नहीं ठहराएगा। यह कूटनीति के भेष में दैवीय अपवादिता को बर्दाश्त नहीं करेगा।

अब कार्रवाई का समय है - न केवल फिलिस्तीन के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के भविष्य के लिए।

दो-राज्य समाधान का भ्रम

जब गाजा में नरसंहार अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो विश्व भर की कई सरकारों ने प्रतीकात्मक इशारों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है - सबसे उल्लेखनीय है **सितंबर में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने** की नवीनीकृत मांग। हालांकि, यह देर से की गई मान्यता, विनाशकारी हिंसा के सामने, न्याय का गंभीर कार्य नहीं है - यह **गैसलाइटिंग है, अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता को खाली घोषणाओं के साथ छिपाने** का एक तरीका है।

दो-राज्य समाधान का विचार ही लंबे समय से मृत है। अब इसे शांति के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि **धुएं के परदे** के रूप में पुनर्जनन किया जा रहा है ताकि इजरायल के अंतिम विनाशकारी कृत्यों को सक्षम किया जा सके।

शर्तों के साथ मान्यता

कई राज्यों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की इच्छा व्यक्त की है - लेकिन **केवल भयानक शर्तों के साथ**:

- **फ्रांस** ने मांग की कि **फिलिस्तीनी निरस्त्र हो जाएं**, प्रभावी रूप से एक घिरे, भूखे और बमबारी किए गए लोगों से **उनके अंतिम प्रतिरोध के साधनों को छोड़ने** की मांग की, जबकि इजरायल अपनी नाकेबंदी और अवैध कब्जा जारी रखता है।
- **यूनाइटेड किंगडम** ने मान्यता को **इजरायल के नरसंहारी हमले की निरंतरता** पर सशर्त किया, यह दावा करते हुए कि मान्यता को "इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करना चाहिए", भले ही यह "रक्षा" **बड़े पैमाने पर भुखमरी, जबरन विस्थापन और सैन्य कब्जे** के रूप में प्रकट हो।

यह मान्यता नहीं है; यह **जबरन आत्मसमर्पण का प्रस्ताव** है। यह फिलिस्तीनियों से मांग करता है कि वे अपनी अधीनता, विखंडन और विनाश को कागज पर मान्यता के मूल्य के रूप में स्वीकार करें - कूटनीति की एक क्रूर पैरोडी।

इस बीच, इजरायल इन राज्यों पर हमला करता है, उन पर " **आतंकवाद को पुरस्कृत करने**" का आरोप लगाता है। लेकिन यह **कड़ाही का बर्तन को काला कहना** है।

इजरायली राज्य की आतंकवादी उत्पत्ति

यदि आतंकवाद की निंदा की जानी है, तो इजरायल की स्थापना को शामिल करना होगा। **सिख्योनवादी अर्धसैनिक समूह** इर्गुन, लेही ("स्टर्न गैंग") और हगनाह - सभी इजरायली रक्षा बल (IDF) के पूर्ववर्ती - ने ब्रिटिश जनादेश के दौरान हिंसक हमलों की एक लहर चलाई:

- **किंग डेविड होटल बम विस्फोट** (1946) में 91 लोग मारे गए।
- **संयुक्त राष्ट्र के दूत फोल्के बर्नाडॉट की हत्या** (1948) लेही द्वारा शांति प्रयासों को रोकने के लिए थी।
- **रोम में ब्रिटिश दूतावास** को 1946 में बमबारी की गई।
- अनगिनत **पुल, बाजार और अरब गांव** पर हमला किया गया और नष्ट कर दिया गया।

आज के मानकों के अनुसार, इन कार्यों को स्पष्ट रूप से **आतंकवाद** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फिर भी, जब इजरायल इस हिंसा से उभरा, तो इसे अलग-थलग या सैंक्शनों का सामना नहीं करना पड़ा - इसे **पश्चिम द्वारा गले लगाया गया**।

संदेश स्पष्ट है: **जब इजरायल हिंसा का उपयोग करता है, तो यह वीरतापूर्ण है**; जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध करते हैं, तो यह आतंकवाद है। यह दोहरा मापदंड अंतरराष्ट्रीय प्रवचन को परिभाषित करता रहता है।

दुनिया के बोलने के दौरान तथ्यों का निर्माण

जब विश्व नेता प्रतीकात्मक मान्यता पर बहस करते हैं, **इजरायल जमीन पर तथ्य बनाना जारी रखता है**:

- **वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में अवैध बस्तियां** बढ़ती जा रही हैं। मान्यता उन्हें **जादुई रूप से गायब नहीं करेगी** और न ही चुराई गई जमीनों को वापस करेगी।
- **गाजा में, हम बोलते समय लोग मर रहे हैं। एकीकृत खाद्य सुरक्षा वर्गीकरण (IPC) ने चरण 5 की विनाशकारी, अपरिवर्तनीय भुखमरी** की घोषणा की है। शिशु, बुजुर्ग और कमजोर **खाद्य की कमी से नहीं, बल्कि इसके जानबूझकर इनकार से मर रहे हैं**।

भले ही भोजन की पहुंच अचानक बहाल हो जाए - जो नहीं हो रहा है - **नुकसान अपरिवर्तनीय है**:

- **बच्चों के दिमाग**, पोषक तत्वों से वंचित, **पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे**, जिससे **जीवन भर की संज्ञानात्मक अक्षमताएं** होंगी।
- **स्कूलों और विश्वविद्यालयों** को व्यवस्थित रूप से बमबारी की गई है, जिसने एक पूरी पीढ़ी की शिक्षा तक पहुंच को समाप्त कर दिया है।

- **मनोवैज्ञानिक आघात**, अनाथता और बड़े पैमाने पर अंग-विच्छेद ने आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व दर्द की विरासत बनाई है। **गाजा में अब दुनिया में बच्चों की सबसे अधिक संख्या में अंग-विच्छेद हैं** - एक भयानक रिकॉर्ड जिसे किसी को नहीं रखना चाहिए।

यह सुझाव देना कि फिलिस्तीनी **इसके सामने निरस्त्र हो जाएं** शांति का प्रस्ताव नहीं है - यह एक **आत्मघाती समझौता** है। पृथ्वी पर कोई भी राष्ट्र अपने हथियार डालने के लिए सहमत नहीं होगा जब उसे व्यवस्थित रूप से भूखा रखा जाता है, बमबारी की जाती है और मिटाया जाता है।

मान्यता उपनिवेशीकरण को नहीं रोकती

राज्य का दर्जा भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। **सीरिया** एक मान्यता प्राप्त राज्य था जब इजरायल ने **गोलन हाइट्स पर कब्जा किया और फिर उसे विलय कर लिया। लेबनान और ईरान** दोनों इजरायली हवाई हमलों, हत्याओं और तोड़फोड़ का निशाना बने हैं। **मान्यता ने कभी आक्रामकता को नहीं रोका**, जब आक्रामक को पूर्ण दण्डमुक्ति प्राप्त हो।

और यह दिखावा करना कि गाजा और वेस्ट बैंक दो अलग-अलग समस्याएं हैं, पूरी तरह से गलत है। वे **एक ही युद्ध के दो मोर्चे हैं** - **फिलिस्तीनी लोगों को मिटाने** का युद्ध:

- **गाजा भुखमरी और बमबारी के माध्यम से उन्मूलन** का सामना करता है।
- **वेस्ट बैंक उपनिवेशकों की हिंसा, पानी की चोरी, सैन्य कब्जे और रेंगते हुए विलय** द्वारा दबाया जाता है।

दोनों **उन्मूलन** की एक समन्वित रणनीति का हिस्सा हैं।

वर्चस्व के तहत सह-अस्तित्व संभव नहीं है

दुनिया यह कैसे उम्मीद कर सकती है कि फिलिस्तीनी उनके साथ सह-अस्तित्व में रहें जो:

- **खुले तौर पर उनके नरसंहार की मांग करते हैं;**
- **उनके बच्चों की हत्या करते हैं;**
- **उनका पानी चुराते हैं;**
- **और उनके खंडहरों पर घर बनाते हैं?**

यदि निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है, तो इसे **इजरायल** से शुरू करना होगा - कब्जे वाली शक्ति, परमाणु हथियारों का धारक और इस रंगभेद शासन का वास्तुकार। यदि उपनिवेशक उन लोगों की उपस्थिति में "असुरक्षित" महसूस करते हैं जिन्हें उन्होंने विस्थापित किया है, तो वे उन देशों में वापस लौटने के लिए स्वागत हैं जहां से वे आए।

निर्मित इतिहास

सिख्योनवादी उपनिवेशीकरण से पहले, **यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य** के तहत सदियों तक सह-अस्तित्व में रहे। यह नाजुक सह-अस्तित्व **फिलिस्तीनियों द्वारा नहीं तोड़ा गया**, बल्कि **राजनीतिक सिख्योनवाद की विचारधारा** द्वारा, जो पहले से बसे हुए क्षेत्र पर एक यहूदी राज्य बनाने की मांग करती थी।

1933 में, सिख्योनवादी आंदोलन ने **नाजी जर्मनी** के साथ **हावरा समझौता** भी किया, जिसने आर्थिक सहयोग के बदले में हजारों जर्मन यहूदियों को फिलिस्तीन में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की - यूरोप में यहूदी फासीवाद-विरोधी प्रतिरोध के लिए एक विश्वासघात।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैविक नहीं था:

- **1917:** ~95% फिलिस्तीन अरबी बोलते थे; **1% से कम हिब्रू बोलते थे।**
- **1922:** ~6% हिब्रू बोलते थे।
- **1931:** ~12%।
- **1947:** ~31%।

यह “वापसी” नहीं थी - यह एक **उपनिवेशी बस्ती परिवर्तन** था।

जैसा कि इजरायली टिप्पणीकार **एवी ग्रिनबर्ग** ने X पर उदासीनता से टिप्पणी की:

“यूनाइटेड किंगडम: हम सितंबर में एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे।” “ठीक है। सितंबर तक, ईश्वर की इच्छा से, मान्यता देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।”

हम इस रास्ते पर हैं। और जब तक दुनिया अब कार्य नहीं करती - केवल शब्दों से नहीं, बल्कि **परिणामों** के साथ - यह भविष्यवाणी साकार हो सकती है।

निष्कर्ष: तटस्थता का युग समाप्त हो गया है

दुनिया ने कहा **“फिर कभी नहीं”**। यह एक सार्वभौमिक वादा होना था - न केवल एक नरसंहार के पीड़ितों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए, हर जगह, हमेशा। यह वादा अब गाजा के खंडहरों और वेस्ट बैंक के बुलडोजरों द्वारा नष्ट किए गए गांवों के नीचे खंडहरों में पड़ा है।

सबूत भारी हैं। फिलिस्तीन में जो हो रहा है वह “संघर्ष” नहीं है। यह “विवाद” नहीं है। यह एक लोगों को मिटाने का एक जानबूझकर, व्यवस्थित प्रयास है - भुखमरी, विस्थापन, बमबारी, पारिस्थितिक विनाश और रंगभेद कानूनों के माध्यम से। गाजा भूखा मर रहा है। वेस्ट बैंक को एक-एक गांव करके तोड़ा जा रहा है। एक साथ, वे उपनिवेशीकरण और उन्मूलन की एक एकल परियोजना बनाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट है। ICJ ने फैसला सुनाया है। संधियां लिखी गई हैं। संधियां बाध्यकारी हैं। जो कमी है वह ज्ञान नहीं है - यह **इच्छाशक्ति** है। और कहीं भी यह विफलता **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में अधिक स्पष्ट नहीं है, जो **संयुक्त राज्य के वीटो** द्वारा पंगु बना दिया गया है, जिसने इजरायल को जवाबदेही से बचाया है और इसके अपराधों को सक्षम किया है।

लेकिन आगे का रास्ता अभी भी मौजूद है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रस्ताव 377 (“शांति के लिए एकजुट”) के अनुसार, जब सुरक्षा परिषद किसी स्थायी सदस्य के वीटो के कारण कार्य करने में विफल रहती है, तो महासभा के पास **इस पक्षाघात को पार करने** की कानूनी प्राधिकार है। यह एक विशेष सत्र बुला सकती है और **सामूहिक कार्रवाइयों** की सिफारिश कर सकती है, जिसमें **बल का उपयोग** शामिल है, शांति बहाल करने और उन आबादी की रक्षा करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों का सामना कर रही हैं।

महासभा को इस शक्ति का उपयोग **अब** करना चाहिए।

उसे चाहिए:

- **यह स्वीकार करना कि एक नरसंहार चल रहा है;**
- **वेस्ट बैंक में रंगभेद शासन की निंदा करना;**
- **फिलिस्तीनी नागरिकों की सैन्य सुरक्षा को अधिकृत करना;**
- **और इजरायल के नाकेबंदी, कब्जे और बस्ती विस्तार को तत्काल समाप्त करने की मांग करना।**

यह कट्टरपंथी नहीं है। यह कानूनी है। यह आवश्यक है। और यह लंबे समय से अतिदेय है।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की राख में हुई थी। इसका चार्टर उन भयावहताओं को रोकने के लिए लिखा गया था जो हम अब देख रहे हैं। यदि यह अब कार्य नहीं कर सकता, जब बच्चों को जानबूझकर भूखा रखा जाता है और पूरे शहरों को दण्डमुक्ति के साथ मिटाया जाता है, तो यह अपनी मूलभूत मिशन में विफल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चुनना होगा: **क्या यह कानून, न्याय और मानवता के पक्ष में खड़ा होगा - या अपवादिता, पाखंड और नरसंहार के पक्ष में?**

फिलिस्तीन एक परीक्षा है। और इतिहास देख रहा है।